इस्पात का उत्पादन

775. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और वर्तमान में देश में स्टेनलैस स्टील की मांग की तुलना में इसका उत्पादन कितना हैं ;

(ख) इस्पात के उत्पादन में उपलब्ध उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण है ; और

(ग) भारत में उत्पादित इस्पात की तुलना में विदेशों में उत्पादित इस्पात के सस्ते और अच्छी क्वालिटी के होने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) देश में तैयार इस्पात के उत्पादन मे वर्ष 1983-84 के मुकाबले में वर्ष 1984-85 में 3 प्रतिशत, वर्ष 1984-85 के मुकाबले में वर्ष 1985-86 में 18 प्रतिशत और वर्ष 1985-86 के मुकाबले में वर्ष 1986-87 में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्टेनलैस स्टील के उत्पादन और मांग के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में क्षमता के उपयोग में कमी के लिए उत्तरदायी कारणों में ये कारण सम्मिलित है—कच्चे माल की घटिया क्वालिटी, पुरानी प्रौद्योगिकी, पुराने उपस्कार, बिजली की सप्लाई में कमी और प्रबंधक-कर्मचारी संबंधों की समस्याएं। "सेल" के कारखानों में कार्य-संस्कृति और सामान्य उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रयास किये गये हैं।

(ग) अन्य देशों में उत्पादित इस्पात के देशीय मूल्य भारत में उत्पादकों के मूल्यों के तुलनीय हैं। भारतीय इस्पात के मूल्यों की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तुलना करना संभव नही है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्याप्त अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा में, निर्यात बढ़ाने के लिए रणनीति के रूप में प्रायः कम कर दिया जाता है। भारत में एकीकृत इस्पात कारखानों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले इस्पात की क्वालिटी भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित ग्रेडों के अनरूप है।

राजभाषा के कार्यान्वयन में रूपरेखा

776. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुई हैं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा कितने प्रतिशत कार्य राजभाषा में किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी सलाहकार समिति तथा राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा की उपेक्षा करते है और अन्य विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में जानबूझ कर विलम्ब करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मंत्रालय सभी विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों में संसद के आधा दर्जन सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिये जिम्मेदार है ; और

(घ) क्या इस मंत्रालय ने 61 हिन्दी सलाहकार समितियों में से 29 में संसद सदस्यों को नाम-निर्देशित नहीं किया है और इस कारण अभी तक उनका गठन नहीं हो पाया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) संसदीय कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पहली बार गठन 18-8-1984 को हुआ।

समिति की अभी तक सात बैठकें हो चुकी हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यो द्वारा राजभाषा में किए गए कार्य के प्रतिशत का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन नही किया गया है।

(ख) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति और राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा की उपेक्षा नहीं करते है । अन्य मंत्रालयो/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में जानबूझ कर विलम्ब का प्रश्न नही उठता है क्योंकि इनका गठन संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से निवेदन प्राप्त होने पर यह मंत्रालय 2 लोक सभा सदस्य और 2 राज्य सभा सदस्य को संबंधित मंत्रालय/विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति पर नामित करता है।

(घ) आठवी लोक सभा के गठन से इस मंत्रालय मे 39 मंत्रालयो/विभागो से उनकी सलाहकार समिति पर संसद सदस्यों के नामांकन के लिए निवेदन प्राप्त हुए है। इस समय मंत्रालय मे किसी भी मंत्रालय/विभाग का हिन्दी सलाहकार समिति पर संपेद सदस्यो के नामांकन के लिए कोई निवेदन लम्बित

Conversion of Agriculture Land for Construction A of Flats

777. SHRI KAILASH PATI MlSHRA. Will the Minister o£ URBAN DEVELOP- MENT be pleased to'state.

(a) whether it is a fact that some cooperative group housing socieites got agriculture, land converted for construction of Cooperative XSroup Housing Flats; and

(b) if $_{SOj}$. what are tfie details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH); (a) and (b) Some cooperative Group Housing Societies have been allotted land by the DDA in the area" shown asAgricul- i tural green belt" in Master Plan for Delhi 1962. The case for change of land use is
- under process as a part of the finalisation of the Perspective Development Plan for Delhi-2001. ..

Post-Harvest HandBng Facilities (for Foodgrains

778. SHRI RAM AWADHESH SINGHSHRI VIRENDRA VERMA: 1

'Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what has been. the percentage with y, alue of the foodgrains output lost, annu-,, ally due toMade of post-harvest handling facilities during the last, three. years and the current year till date; and

- <b). what efforts have been made -by Government in the field of research. and Heyelopment of infrastructure and technology for handling the faflm produce keeping in pace with the increase in pro-
- ' duction and thereafter transferring it to the fields stating the results achieved so far.

THE MINISTER OF STATE IN THE. MINISTRY OF FOOD AND, CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NAB1 AZAD); (a) No systematic|comprehen-sive studies to asses the foodgrains lost annually due to lack of the post-harvest handling facilities have been made However, the Expert Committee of Govern-
ment of India on post-harvest, losses in 1966 had estimated that about *9* per cent was post during post-harvest operations and storage.

(b) The Research. Development and Training for improving the storage conditions of foodgrains are being undertaken at the Indian Grain Storage Institute, Ha-pur with its five field stations in the country. In addition. 17 regional Central Save Grain teams have been set up t_0 give a lead to the States and play a catalytic role in the tiissemination of improved storage practices for better 'preservation of foodgrains at the farm leveL The 'major planks, of the campaign are: Training Demonstration and Publicity in selec-